Industries is also implementing various Plan Schemes under which financial assistance is provided to State Governments/Joint Sector/ Cooperative Sector etc.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजना

3838 . **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सहित सभी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास कम होने के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं बनाई गई है;

(ख) क्या इस स्थिति के परिणामस्वरूप निजी निवेशकों द्वारा निवेश नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में वर्ष 1996-97 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) :

(क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश भर में इसमें त्रिपुरा शामिल है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए आठवीं योजना के दौरान अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें बनाई और लागू की हैं। नौवीं योजना अवधि के दौरान भी ऐसी स्कीमों को लागू करने का प्रस्ताव है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष।

जुलाई, 1991 से अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों और अनुमोदनों के मार्फत लगभग 7700 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश समेत मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा 63200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं में से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश की परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा चुका है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण के विकास के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों, संयुक्त क्षेत्र/ सहायता प्राप्त परियोजनाओं, स्वयंसेवी एजेंसियों, सहकारिताओं, निजी उद्यमियों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। 1996-97 के दौरान हमारी स्कीमोम के लिए परिव्यय 40 करोड़ रुपये था।

मध्य प्रदेश में आम प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता दिया जाना

3839. **श्री अजीत जोगी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में आम प्रसंस्करण उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाएं स्वीकृति हेतु सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मध्य प्रदेश समेत देश में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों, इसमें आम प्रसंस्करण उद्योग शामिल है, की स्थापना/विस्तार/उन्हें बेहतर बनाने के वास्ते सहायता उपलब्ध कराने हेतु फल तथा सब्जी,प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनेक विकास योजना स्कीमें चला रहा है। ये स्कीमें राज्य विशेष नहीं होतीं। वैसे मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग को बढावा दिया जाना

3840. **श्री एस.एस** अहलुवालिया :क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी तथा ग्रामोद्योग को बढावा देने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है और उसे लागू किया है,;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार में ग्रामोद्योगों को बढावा देने में आयोग की अब तक क्या भूमिका रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) बिहार राज्य सहित पूरे देशभर में यथासंभव अधिकाधिक जीव्यक्षम खादी तथा ग्रामोद्योग एककों को बढावा देने की खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की कोशिश रही है । उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार 2002 ई. सन् के अन्त तक के वी आई क्षेत्र में 5.6 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार सृजित करने के लिए खादी तथा